Schemes for Developoment and Export of Handicrafts and Handloom Products

372. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAIPATEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up any scheme for the development and export of handicrafts and handloom products in Gujarat;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken in this regard during the remaining period of 8th five year Plan.

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R. L. JALAPPA): (a) and (b) No seperate scheme have been drawn up for the development and export of handicrafts and handlooms products in Gujarat. However for the overall development and export of handicrafts and handlooms in the country including the State of Gujarat, the Government through State corporation/Apex Societies/Primary Societies and Voluntary Organisations are implementing various schemes. The schemes include: organisation of marketing programmes; marketing development support; setting of crafts/handloom development centres; project package; training; design development; handloom development under rural development programmes like IRDP, IAY, JRY and TRYSEM: margin money for destitute weavers; workshed-cum-housing; thrift fund; group insurance; health package; sponsoring sales-cum-study team abroad; participation in fairs/festivals; organisation of buye-seller meet; conducting of seminars and workshops.

(c) All the existing schemes mentioned in reply to part (a) and (b) of the question will be continued in the remaining period of 8th Plan.

Possible U.S. sanctions against India

373. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether India is facing with a possible US sanctions for building a pesticide plant in Iran;

(b) if so, whether Government have received any indications from the U.S. in this regard; if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) No, Sir.

(b) US Administration have conveyed their apprehension about the possibility of the pesticide plant being used for chemical weapon purposes.

(c) Government have conveyed that India is committed to non-proliferation of chemical weapons and honouring its international commitment under the Chemical weapons convention to which it is a signatory.

दिल्ली में द्रुत गति वाली ट्राम चलाने की योजना

374. **श्री राघवजी:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में द्रुत गति वाली ट्राम चलाने की योजना आरंभ करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो योजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दिल्ली की यातायात समस्या हल करने के लिए कोई वैकल्पिक योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी० जी० वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली में द्रुत गति वाली ट्राम चलाए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

फिलहाल यह बता पाना संभव नहीं है कि इस स्कीम को कब तक शुरू कर दिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। दिल्ली में तीव्र जन परिवहन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए प्रथम चरण में मार्ग का संरेखण नीचे दर्शाया गया है:—

दिल्ली विश्व विद्यालय-आई एस बी टी-कनाट प्लेस-केन्द्रीय सचिवालय	11.00 कि०मी०
शाहदरा-आई एस बी टी-रामपुरा-नांगलोई	25.00 कि०मी०
सब्जी मंडी-नया आजादपुर-होलम्बी कलां	19.30 कि०मी०
कुल	55.30 कि०मी०

नियत मूल्यों पर (1994-95 का मूल्य स्तर) इस परियोजना की संशोधित लागत 4182 करोड़ रु० है तथा वर्तमान मूल्यों (अप्रैल, 95) पर (भूमि की लागत सहित) संशोधित लागत 6313 करोड़ रु० है। इस परियोजना के चरण-1 की कुल निर्माण अवधि, लगभग 10 वर्ष होने का अनुमान है।

वर्ष 1995-96 के दौरान खोले गए डाकघर

375. **श्री नागमणि:**
श्री ईशदत्त यादव:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य-वार नए डाकघर खोलने हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से अब तक राज्य-वार कितने डाकघर खोले जा चुके हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) वर्ष 1995-96 के दौरान जितने नए डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उनकी सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) इनमें से अब तक जितने डाकघर खोले जा चुके हैं, उनकी सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य

क्रम सं०	सर्किल का नाम	लक्ष्य अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	लक्ष्य विभागीय उप डाकघर
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	5
2.	असम	4	4
3.	बिहार	10	11
4.	दिल्ली	—	10
5.	गुजरात	4	12
6.	हरियाणा	2	10
7.	हिमाचल प्रदेश	7	10
8.	जम्मू एवं कश्मीर	—	2
9.	कर्नाटक	1	10
10.	केरल	1	9
11.	मध्य प्रदेश	9	9
12.	महाराष्ट्र	9	12
13.	उत्तर पूर्व	4	4
14.	उड़ीसा	4	4
15.	पंजाब	2	4
16.	राजस्थान	5	10
17.	तमिलनाडु	2	4
18.	उत्तर प्रदेश	12	16
19.	पश्चिम बंगाल	2	4
	कुल:	80	150

टिप्पणी: उत्तर पूर्व डाक सर्किल के अंतर्गत मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। इसी प्रकार, गोवा राज्य महाराष्ट्र सर्किल के अन्तर्गत आता है। सिक्किम राज्य पश्चिम बंगाल सर्किल के अन्तर्गत आता है।

विवरण-II

वर्ष 1995-96 के दौरान खोले गए डाकघर

क्रम सं०	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	3
2.	असम	—	1